(b) and (c) The Government intends to expand the scope of the Scheme to include other categories of taxpayers and to expand the facility to include more intermediaries as well as cover more cities.

श्री आरएपी गोयंका: सर, मेरा निवेदन है कि यह बहुत वेलकम स्टेप है और इसमें कोई डाउट नहीं है लेकिन इसका टाइम फ्रेम क्या है और इसको पापुलर करने के लिए आप क्या कार्यवाही कर रहे हैं?

श्री जसवंत सिंह: सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने कहा है कि स्कीम अच्छी है और टाइम फ्रेम क्या है। यह असीमित है, चलती रहेगी। लक्ष्य तो यह है कि सभी टैक्सपेयर इसके जरिये अपने टैक्स की रिटर्न फाइल करें। बड़ा अच्छा होगा। इसको आगे बढ़ाने के लिए हम क्या कर रहे हैं- जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं कि अभी हमने कुछ चुनिंदा शहरों में ही इसे शुरू किया है, मसलन-अहमदाबाद, बंगलौर, चैन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता और मुम्बई में। हमारा विचार है कि यह फैसला चाहिए।

दूसरी बात, मैं एक मिनट का समय लेकर बता देता हूं कि अभी तक करीब 1135 ऐसेसी अपने आप आगे आये हैं जिन्होंने इस जरिये से अपनी रिटर्न भरना शुरू किया है। हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग ऐसा करें। इसके लिए हम इंटरमीडियरीज़ को बढ़ा रहे हैं। जो एम्पलायर हैं उनके यहां यह भरी जा सकती है। इसके अलावा चारटर्ड एकाउटेंट हैं, टैक्स एडवोकेट्स हैं, उनके यहां भी रिटर्न भरी जा सकेंगी। ऐसा करके हमारा लक्ष्य है कि इस स्कीम को धीरे-धीरे बढ़ाया जाये।

भू-जल स्तर

*210 **श्री जनेश्वर मिश्र:** क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि देश में भू-जल स्तर बहुत अधिक घट रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) भू-जल स्तर को ऊपर लाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

जल संसाधन मंत्री (श्री अर्जुन चरण सेठी): (क) से (ग) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) जल संसाधन मंत्रालय के अंतर्गत, केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड (सी जी डब्ल्यू बी) द्वारा वर्ष 1983-2002 के दौरान भूजल स्तरों के दीर्घकालिक विश्लेषण से देश के विभिन्न राज्यों के कुछ जिलों में भूजल स्तर में 4 मीटर से अधिक की गिरावट का पता चला है। उन राज्यों/जिलों के नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं जहां के पाकेटों में विगत बीस वर्षों (1983-2002) में जल स्तर में गिरावट आई है। (**नीचे** देखिए)

(ग) सिंचाई, राज्य का विषय होने के कारण जल संसाधनों के संवर्द्धन के लिए स्कीमों की आयोजना, वित्तपोषण और उनके कार्यान्वयन का उत्तरदायित्व मुख्यत: संबंधित राज्य सरकारों का है। केन्द्र सरकार ने भूजल के अति दोहन को रोकने के लिए निम्नलिखित उपाय शुरू किए हैं:

(i) देश में भूजल के पुनर्भरण के अध्ययन के लिए केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम का कार्यान्वयन।

(ii) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण संबंधी मैनुअल/मार्गदर्शन का परिचालन करना ताकि वे भूजल स्तर में गिरावट की प्रवृत्ति को रोकने के लिए क्षेत्र विशिष्ट कृत्रिम पुनर्भरण स्कीमें तैयार कर सकें।

(iii) सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वर्ष 1970 में माडल बिल का परिचालन, जिसे वर्ष 1992 और 1996 में दोबारा पुन: परिचालित किया गया था, ताकि वे भूजल विकास के विनियमन और नियंत्रण के लिए उपयुक्त कानून बना सकें।

(iv) वर्षा जल के संचयन और भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण पर जन जागरूकता कार्यक्रम और प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का आयोजन।

(v) भूजल के प्रबंधन और विकास के विनियमन और नियंत्रण के लिए पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 के तहत केन्द्रीय भूमि जल प्राधिकरण का गठन।

(vi) वर्षा जल संचयन की विभिन्न तकनीकों और भविष्य में उपयोग के लिए इसका भंडारण करने के बारे में लोगों को जागरूक और शिक्षित करने के लिए छत के वर्षा जल संचयन संबंधी वेबसाइट (**डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू.सीजीडब्ल्यूबीडॉटइंडियाडॉटकाम**) शुरू करना।

विवरण-I

मानसून पूर्व अवधि के दौरान पिछले 20 वर्षों (1983—2002) में जल स्तरों (भागों में) जल स्तर की गिरावट दर्शाने वाले जिलों के नाम

क्र॰ सं॰	राज्य	4 मीटर से अधिक की गिरावट दर्शाने वाले जिले (20 सेमी प्रति वर्ष से अधिक की दर से)
1.	आंध्र प्रदेश	अदिलाबाद, अनन्तपुर, चित्तूर, कुडप्पा, पूर्वी गोदावरी, गुन्टूर, हैदराबाद, करीमनगर, कुरनूल, महबूबनगर मेडक, नालागोंडा, नेल्लोर, निजामाबाद, प्रकाशम, रंगा रेड्डी, श्रीकाकुलम, विशाखापट्टनम, विजियानगरम, वारंगल, पश्चिमी गोदावरी।
2.	अरुणाचल प्रदेश	सियांग पूर्व।
3.	असम	जोरहाट, करबी अंगलोंग, मोरीगांव।
4.	बिहार	दरभंगा, गया, खगड़िया समस्तीपुर।
5.	छत्तीसगढ़	बस्तर, बिलासपुर, दांतीवाड़ धमतरी, दुर्ग जंजगीर चम्पा, कंकेर, कोरबा, रायगढ़।
6.	दिल्ली	मध्य, नई दिल्ली, उत्तर पश्चिम, दक्षिण, दक्षिण पश्चिम, पश्चिम।
7.	गुजरात	अहमदाबाद, अमरेली, बनासकांठा, बड़ौदा, भरूच, भावनगर, डांग्स, जामनगर, जूनागढ़, खेड़ा, कच्छ, मेहसाना, पंचमहल, राजकोट, साबरकांठा, सूरत, सुरेन्द्रनगर, बलसाड।
8.	हरियाणा	भिवानी, फरीदाबाद, गुड़गांव, हिसार, जींद, कैथल, कुरूक्षेत्र, महेन्द्रगढ़ पंचकुला, पानीपत, रेवाड़ी, सिरसा।
9.	झारखंड	गुमला, पलामू।
10.	कर्नाटक	बंगलौर, बेल्लारी, बेलगाम, बीदर, बीजापुर, चित्रदुर्ग, देवनगिरि, धारवाड़ गदग, गुलबर्गा, हासन, हवेरी, कोलार, कोप्पाला, मांड्या मैसूर, रायचूर, शिमोगा, तुमकुर, उत्तर कन्नड़।
11.	केरल	इडुकी, कन्नुर, कोल्लम।

क्र॰ सं॰	राज्य	4 मीटर से अधिक की गिरावट दर्शाने वाले जिले (20 सेमी प्रति वर्ष से अधिक की दर से)
12.	मध्य प्रदेश	बरवानी, बेतुल, भिन्ड, भोपाल, छतरपुर, दामोह, दतिया, देवास, धार, गुना, ग्वालियर, होशंगाबाद, इंदौर, जबलपुर, झाबुआ, कटनी, खण्डवा, खरगौन, मंदसौर, मुरैना, नरसिंहपुर, नीमच, पन्ना, रायसेन, राजगढ़, रतलाम, रीवा, सागर, सतना, सीहोर, शाजापुर, शिवपुर, शिवपुरी, टीकमगढ़, उज्जैन, विदिशा, छिंदवाड़ा।
13.	महाराष्ट्र	अहमदनगर, अकोला, अमरावती, औरंगाबाद, भंडारा, बुलदाना, चंद्रपुर, धुले, गढ़चिरौली, जलगांव, जालना, कोल्हापुर, लातूर, नागपुर, नार्देड़, नासिक, ओस्मानाबाद, परभनी, पुणे, रायगढ़, रत्नागिरी, सांगली, सतारा, सोलापुर, थाने, वर्धा, यावतमल।
14.	मेघालय	पश्चिम गारो पहाड़ियां।
15.	उड़ीसा	अंगुल, बालासोर, बारगढ़, बोलंगीर, कटक, देवगढ़, धेनकनाल, गजपति, गंजम, जजपुर, कालाहांडी, खुर्दा, कोरापुट, मल्कानगिरी, मयूरभंज, नवापाड़ा, नयागढ़, नौरंगपुर, फुलबनी, पुरी, रायगदा, संबलपुर, सोनपुर, सुंदरगढ़।
16.	पंजाब	अमृतसर, भटिन्डा, फरीदकोट, फतेहगढ़, फिरोजपुर, जालंधर, कपूरथला, लुधियाना, मन्सा, मोगा, पटियाला, रोपड़, संगरूर।
17.	राजस्थान	अजमेर, अलवर, बांसवाड़ा, बरन, बाड़मेर, भीलवाड़ा, बीकानेर, बूंदी, चित्तौड़गढ़, चुरू, दौसा, धौलपुर, डूंगरपुर, गंगानगर, हनुमानगढ़, जयपुर, जालौर, झालावाड़, झुनझुनु, जोधपुर, करौली, कोटा, नागौर, पाली, राजसमन्द, सवाई माधोपुर, सीकर, सिरोही, टोंक उदयपुर।
18.	तमिलनाडु	चेन्नई, कोयंबतूर, कुड्डालोर, धरमपुरी, डिंडीगुल, एरोड, कांचीपुरम, कन्याकुमारी, कराईकल, नमक्कल, पेरम्बदूर, पुदुकोट्टई, रामनाथपुरम, शिवगंगा, तंजावूर, थेनी, तिरूचिरापल्ली, तिरूनेलवेली, तिरूवेल्लूर, तिरूवन्नामलाई, तिरूवरूर, विलुप्पुरम।

क्र.सं॰	राज्य	4 मीटर से अधिक की गिरावट दर्शाने वाले जिले (20 सेमी प्रति वर्ष से अधिक की दर से)
19.	उत्तर प्रदेश	आगरा, अलीगढ़, इलाहाबाद, आजमगढ़, बदायूं, बहराइच, बलिया, बांदा, बाराबंकी, बरेली, बुलंदशहर, देवरिया, एटा, इटावा, फैजाबाद, फतेहपुर, गाजियाबाद, गोंडा, हमीरपुर, हरदोई, जालौन, जौनपुर, झांसी, कानपुर, लखीमपुर, ललितपुर, लखनऊ, मैनपुरी, मथुरा, मेरठ, मिर्जापुर, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, प्रतापगढ़ रायबरेली, रामपुर, सहारनपुर, शाहजहांपुर, सीतापुर सुल्तानपुर, उन्नाव।
20.	पश्चिम बंगाल	बांकुड़ा, बर्धमान, बीरभूम, दक्षिण दीनाजपुर, हावड़ा, हुगली, जलपाईगुड़ी, मेदनीपुर, मुर्शिदाबाद, उत्तर 24 परगना, पुरूलिया, दक्षिण 24 परगना।

Ground water level

†*210. SHRI JANESHWAR MISHRA: Will the Minister of WATER RESOURCES be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the ground water level is decreasing considerably in the country;

(b) if so, the details thereof; and

(c) what steps are being taken by Government for raising the ground water level?

THE MINISTER OF WATER RESOURCES (SHRI ARJUN CHARAN SETHI): (a) to (c) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) and (b) A long-term analysis of ground water levels by the Central Ground Water Board (CGWB), under the Ministry of Water Resources during the years 1983-2002 indicates decline in ground water levels by

†Original notice of the question was received in Hindi.

more than 4 metres in some districts of various States of the country. The names of the States/districts having pockets with fall in water level in the last twenty years (1983-2002) are given in the enclosed Statement (*See* below).

(c) Water being a State subject, it is primarily the responsibility of the concerned State Governments to plan, finance and execute schemes for augmenting water resources. The Central Government has initiated following measures to check over-exploitation of ground water:—

(i) Implementation of a Central Sector Scheme for Study of Recharge to Ground Water in the country.

(ii) Circulation of Manual/Guidelines on Artificial Recharge of Ground Water to the States/Union Territories to enable them to formulate area specific artificial recharge schemes to check the declining trend in ground water levels.

(iii) Circulation of a Model Bill in the year 1970 which was re-circulated in 1992 and again in 1996 to all the States/Union Territories to enable them to enact suitable legislation for regulation and control of ground water development.

(iv) Organisation of mass awareness programmes and training courses on rain water harvesting and artificial recharge of ground water.

(v) Constitution of Central Water Authority under the Environment (Protection) Act, 1986 for regulation and control of ground water management and development.

(vi) Launching of a website on Roof Top Rain Water Harvesting (*www.egwbindia.com*) to make aware and educate the public about various techniques of harvesting rainwater and store it for future use.

Statement

Name of Districts showing fall of water level (in parts) in last 20 years (1983-2002) during Pre-Monsoon period

S.No.	State	Districts showing Fall of More than 4m. (@ more than 20 cm per year)
1.	Andhra Pradesh	Adilabad, Anantapur, Chittoor, Cuddaph, East Godavari, Guntur, Hyderabad, Karimnagar, Kurnool, Mahbubnagar, Medak, Nalgonda, Nellore, Nizamabad, Prakasam, Ranga Reddy, Srikakulam, Visakhapatnam, Vizianagaram, Warangal, West Godavari
2.	Arunachal Pradesh	East Siang
3.	Assam	Jorhat, Karbi Anglong, Morigaon
4.	Bihar	Darbhanga, Gaya, Khagaria, Samastipur
5.	Chhattisgarh	Bastar, Bilaspur, Dantewada, Dhamtari, Durg, Janjgir-champa, Kanker, Korba, Raigarh
6.	Delhi	Central, New Delhi, North West, South, South West, West
7.	Gujarat	Ahmedabad, Amreli, Banashkantha, Baroda, Bharuch, Bhavnagar, Dangs, Jamnagar, Junagarh, Kheda, Kutch, Mehsana, Panch Mahal, Rajkot, Sabarkantha, Surat, Surendra-nagar, Valsad
8.	Haryana	Bhiwani, Faridabad, Gurgaon, Hissar, Jind, Kaithal, Kurukshetra, Mahendragarh, Panchkula, Panipat, Rewari, Sirsa
9.	Jharkhand	Gumla, Palamu
10.	Karnataka	Bangalore, Belary, Belgaum, Bidar, Bijapur, Chitradurga, Davanagere, Dharwad, Gadag, Gulbarga, Hassan, Haveri, Kolar, Koppala, Mandya, Mysore, Raichur, Shimoga, Tumkur, Uttar Kannada

S.No.	State	Districts showing Fall of More than 3m. (@ more than 20 cm per year)
11.	Kerala	Iduki, Kannur, Kollam.
12.	Madhya Pradesh	Barwani, Betul, Bhind, Bhopal, Chhatarpur, Damoh, Datia, Dewas, Dhar, Guna, Gwalior, Hoshangabad, Indore, Jabalpur, Jhabua, Katni, Khandwa, Khargone, Mandsaur, Morena, Narisinghpur, Nimuch, Panna, Raisen, Rajgarh, Ratlam, Rewa, Sagar, Satna, Sehore, Shajapur, Sheopur, Shivpuri, Tikamgarh, Ujjain, Vidisha, Chhindwara.
13.	Maharashtra	Ahmadnagar, Akola, Amravati, Aurangabad, Bhandara, Buldana, Chandrapur, Dhule, Gadchiroli, Jalgaon, Jalna, Kolhapur, Latur, Nagpur, Nanded, Nashik, Osmanabad, Parbhani, Pune, Raigarh, Ratnagiri, Sangli, Satara, Solapur, Thane, Wardha, Yavatmal.
14.	Meghalaya	West Garo Hills
15.	Orissa	Angul, Balasore, Bargarh, Bolangir, Cuttack, Deogarh, Dhenkanal, Gajapati Ganjam, Jajpur, Kalahandi, Khurda, Koraput, Malkangiri, Mayurbhanj, Nawapara, Nayagarh, Nowrangpur, Phulbani, Puri, Rayagada, Sambalpur, Sonepur, Sundargarh.
16.	Punjab	Amritsar, Bhatinda, Faridkot, Fatehgarh, Ferozepur, Jalandhar, Karpurthala, Ludhiana, Mansa, Moga, Patiala, Ropar, Sangrur.
17.	Rajasthan	Ajmer, Alwar, Banswara, Baran, Barmer, Bhilwara, Bikaner, Bundi, Chittorgarh, Churu, Dausa, Dholpur, Dungarpur, Ganganagar, Hanumangarh, Jaipur, Jalore, Jhalwar, Jhunjhunu, Jodhpur, Karauli, Kota, Nagaur, Pali Rajsamand, Sawaimadhopur, Sikar, Sirohi, Tonk, Udaipur.

S.No.	State	Districts showing Fall of More than 3m. (@ more than 20 cm per year)
18.	Tamil Nadu	Chennai, Coimbatore, Cuddalore, Dharmapuri, Dindigul, Erode, Kancheepuram, Kanniyakumari, Karaikal, Namakkal, Perambalur, Pudukkottai, Ramanathapuram, Sivaganga, Thanjavur, Theni, Tiruchirappalli, Tirunelveli Tiruvallur, Tiruvannamalai, Triuvarur, Viluppuram.
19.	Uttar Pradesh	Agra, Aligarh, Allahabad, Azamgarh, Badaun, Bahraich, Ballia, Banda, Barabanki, Bareilly, Bulandshahar, Deoria, Etah, Etawah, Faizabad, Fatehgarh, Fatehpur, Ghaziabad, Gonda, Hamirpur, Hardoi, Jalaun, Jaunpur, Jhansi, Kanpur, Lakhimpur, Lalitpur, Lucknow, Mainpuri, Mathur, Meerut, Mirzapur, Moradabad, Muzaffarnagar, Pratapgarh, Raebareli, Rampur, Saharanpur, Shahjahanpur, Sitapur, Sultanpur, Unnao.
20.	West Bengal	Bankura, Bardhaman, Birbhum Dakshin Dinajpur, Haora, Hugli, Jalpaiguri, Mednipur, Murshidabad, North Twenty four Parganas, Puruliya, South Twenty four Parganas.

श्री जनेश्वर मिश्र: सभापति महोदय, कायदे से और थोड़ी बहुत नैतिकता के नाते इस विभाग से मुझे सवाल नहीं पूछना चाहिए क्योंकि मैं इस विभाग में पहले था और अपने उत्तराधिकारियों को संकट में नहीं डालना चाहिए। लेकिन मैं भी थोड़ा दोषी था, मेरे से पहले के लोग भी दोषी हैं। जमीन के नीचे के पानी का दोहन और उसका प्रचलन इधर 20-25 साल में बहुत बढ़ा है। सभापति महोदय, अगर हम पार्लियामेंट में ट्यूबवैल लगा दें तो राष्ट्रपति भवन के नीचे का पानी भी उस ट्यूबवैल से हम खींच सकते हैं। इसको किसी अपराध की श्रेणी में नहीं लिया जा सकता है। इस तरह से वहां पानी की किल्लत हो जायेगी और हम मौज करेंगे। क्या यह सही है? आप कहते हैं कि पानी राज्य का विषय है और राज्य सरकारें कानून बनायें। राज्य सरकार धरातल के ऊपर के बारे में कानून बनाने के लिए रहेंगी।

धरातल के नीचे जो अपराध पानी को लेकर हो रहे हैं, क्योंकि धरातल के नीचे का पानी ही तो पीने योग्य है, उसके बारे में क्या कभी सरकार विचार करेगी? सरकार उसके ऊपर कोई कानून बनाए और लाइसेंस दे। जो लोग भी नीचे का पानी ट्यूबवैल से या पम्पिंग सेट से लेते हैं, वे बिना परमिशन इन्हें न बनाएं और अगर बनाएं तो उसको अपराध की श्रेणी में लिया जाए।

SHRI ARJUN CHARAN SETHI: Sir, depletion of ground water table is certainly a matter of concern not only to the Government, but also for all of us. So far as the point, whether we are taking any steps for having any legislation to control random extraction of ground water is concerned, yes, we have circulated a model Bill to all the States. And, a few States have enacted legislations also. Many other States are considering it, and are trying to have this kind of legislation so that depletion of ground water could be regulated and random extraction of ground water be stopped. The States, which have already enacted laws in this regard, are Goa, Tamil Nadu, Lakshadweep, Pondicherry, Kerala and Andhra Pradesh. On 19.04.2002, the Government of Andhra Pradesh had already passed the Andhra Pradesh Water and Land Act, 2002. The States of Gujarat, Maharashtra and West Bengal have yet to enact laws in this regard. The States and UTs, which have initiated action for enacting legislation in this regard, are: Assam, Bihar, Haryana, Himachal Pradesh, Jammu & Kashmir, Karnataka, Mizoram, Orissa, Punjab, Rajasthan, Uttar Pradesh, Daman & Diu, and NCT of Delhi. So, more or less, all the State Governments are trying their best to enact laws in this regard. We have also been repeatedly reminding them to have laws in this regard, so that depletion of ground water could be regulated and random extraction of ground water be stopped.

श्री ज्ञनेश्वर मिश्र: सभापति महोदय, हमारे प्रश्न की मंशा थी कि क्या राष्ट्रीय स्तर पर, आईपीसी के तौर पर इस पर कोई कानून बनेगा? माननीय मंत्री जी ने राज्य सरकारों को कहा लेकिन अब मैं उस विषय पर नहीं जा रहा। इधर जब से खेतों में केमीकल्स का इस्तेमाल होता है, जितना भी पानी बरसता है या ऊपर जमीन पर डाला जाता है, वह केमीकल्स से छनकर नीचे जाता है। बहुत से हिस्सों में जहां खाद डाली जाती है, वहां ड्रिंकिंग वाटर, जमीन के नीचे का पानी बहुत ही खराब है, पीने लायक नहीं रह गया। मैं यह तो नहीं कहता कि खेतों में खाद न डाली जाए लेकिन मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि जो नीचे का पानी निकालकर लोग पी रहे हैं और जो पानी नुकसान कर रहा है, उसके बारे में क्या कभी आपने सोचा है और कार्यवाही की है?

श्री सभापति: माननीय मंत्री महोदय, एक बात सुन लीजिए, क्वेश्चन ऑवर खत्म होने वाला है। यह बहुत ही गंभीर विषय है और इससे बहुत लोग पीड़ित हैं। इस क्षेत्र में किस प्रकार से सुधार किया जा सकता है, इस संबंध में जल्दी से जल्दी कोई ऐसी कार्यवाही कीजिए ताकि इस प्रकार की अव्यवस्था न रहे और लोगों को पीड़ा न भोगनी पड़े।

The Question Hour is over.

WRITTEN ANSWERS TO STARRED QUESTIONS

Losses due to Shortage of Aircrafts

†*211. SMT. KUM KUM RAI: Will the Minister of CIVIL AVIATION be pleased to refer to answer to Unstarred Question 17 given in the Rajya Sabha on the 2nd December, 2003 and state:

(a) whether it is a fact that Air India and Indian Airlines have shortage of aircrafts and most of the aircrafts are quite old;

(b) if so, the total number of aircrafts with these companies separately alongwith the age of each aircrafts; and

(c) whether it is also a fact that the two airlines are incurring losses due to shortage of aircrafts, if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF CIVIL AVIATION (SHRI RAJIV PRATAP RUDY): (a) Yes, Sir.

(b) Air India and Indian Airlines are having 31 and 47 aircraft each and with an average age of 14.79 and 15.7 years respectively.

(c) No, Sir. Air India has made a net profit of Rs. 15.44 crores and Rs. 133.85 crores during the financial years 2001-02 and 2002-03 respectively. As regards Indian Airlines, losses incurred by them are not attributable to shortage of aircraft alone.

Special Tourism Areas

*212. SHRI SURENDRA LATH: Will the Minister of TOURISM AND CULTURE be pleased to state:

(a) the places identified in various States for developing them into special tourism areas, State-wise;

---

†Original notice of the question was received in Hindi.